आयकर आयुक्त, पंजाब

बनाम

मैसर्स चंदर भान हरभजन लाल

4 जनवरी, 1966

[ए.के.सारकर, जे.आर.मुधोलकर और आर.एस.बच्छावत, जे.जे.]

आय-कर अधिनियम (1922 का 11)। 66 (2) -एक फर्म का भागीदार भी निर्धारिती फर्म में भागीदार है-क्या पहली फर्म के सभी हिस्सेदार निर्धारिती-फर्म के भागीदार हैं-जो कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल है।

निर्धारिती-फर्म, जिसमें 14 भागीदार शामिल थे, ने धारा 26ए आय-कर अधिनियम, 1922 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया। एक जी, जो निर्धारिती-फर्म का भागीदार था, एक अन्य फर्म, फिरोजपुर फर्म का भी भागीदार था। फिरोजपुर फर्म में 8 भागीदार शामिल थे जो इस बात पर सहमत थे कि यदि उनमें से किसी एक द्वारा दूसरों के साथ कोई काम किया जाता है तो उस काम से होने वाले लाभ और हानि को उस फर्म में उनके शेयरों के अनुपात में सभी भागीदारों के बीच विभाजित किया जाएगा। निर्धारिती-फर्म के पंजीकरण की कार्यवाही के दौरान उसके सभी भागीदारों ने आयकर अधिकारी के समक्ष कहा था कि जी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं बल्कि फिरोजपुर फर्म की ओर से एसेसेस फर्म में भागीदार था, । आय-कर अधिकारी ने पाया कि निर्धारिती फर्म की पूंजी जी द्वारा प्रदान की गई थी, जिसने फिरोजपुर फर्म से राशि ली थी, और निर्धारिती-फर्म को उसी तरह का व्यवसाय करना था जैसा कि फिरोजपुर फर्म को करना था। आयकर अधिकारी ने आवेदन इस कारण से खारिज कर दिया कि वास्तव में यह जी नहीं बल्कि फिरोजपुर फर्म थी जो निर्धारिती-फर्म की भागीदार थी और इसके परिणामस्वरूप, निर्धारिती-फर्म का गठन अवैध रूप से किया गया था क्योंकिः (i)

फिरोजपुर फर्म कानूनी रूप से निर्धारिती-फर्म में भागीदार नहीं हो सकती थी; (ii) निर्धारिती-फर्म के भागीदारों की कुल संख्या तब 21 होगी; और (iii) निर्धारिती-फर्म के साझेदारी विलेख में फिरोजपुर फर्म के भागीदारों के व्यक्तिगत शेयरों को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। अपीलीय सहायक आयुक्त, अपील पर उस आदेश को उलटते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि जी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में निर्धारिती-फर्म का भागीदार था न कि फिरोजपुर फर्म के प्रतिनिधि के रूप में और निर्धारिती-फर्म में अपने लाभ और हानि को फिरोजपुर फर्म के अन्य भागीदारों के साथ साझा करने के लिए उनके समझौते का प्रभाव केवल निर्धारिती-फर्म में जी के हिस्से के संबंध में जी और फिरोजपुर फर्म में अन्य भागीदारों के बीच एक उप-साझेदारी का गठन करना था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलीय सहायक कमिश्नर के आदेश को इस संक्षिप्त आधार पर बरकरार रखा कि उसके द्वारा उद्धृत कुछ निर्णयों को देखते हुए अपील में कोई योग्यता नहीं थी, और धारा 66 (1) के तहत कानून के चार प्रश्नों को उच्च न्यायालय को संदर्भित करने के आवेदन को भी खारिज कर दिया। आयुक्त ने धारा 66 (2) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को संदर्भित करने का न्यायाधिकरण को निर्देश देने के लिए एक याचिका दायर की ; (1) क्या जी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में निर्धारिती-फर्म का भागीदार था या फिरोजपुर, फर्म के भागीदारों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और (2) क्या फिरोजपुर फर्म एक उप-साझेदारी थी; लेकिन उच्च न्यायालय ने आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि विधि के प्रश्न अच्छी तरह से हल किए गए थे।

इस न्यायालय में अपील में यह तर्क दिया गया था किः (i) परिधीय दृष्टिकोण के तहत, जी निर्धारिती-फर्म का भागीदार था-अपनी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं, बल्कि फिरोजपुर फर्म की ओर से; (ii) उच्च न्यायालय ने माना कि इस गलत धारणा पर एक उप-साझेदारी थी कि फिरोजपुर फर्म, निर्धारिती-फर्म के गठन के बाद अस्तित्व में आई थी; और चूंकि एक उप-साझेदारी केवल साझेदारी के

स्थिर होने के बाद ही की जा सकती है, इसलिए फिरोजपुर फर्म के सदस्यों के बीच कोई उप-साझेदारी नहीं हो सकती। और (iii) न्यायाधिकरण आदेश से कानून का प्रश्न उत्पन्न हुआ था ऐसे में उच्च न्यायालय मामले के बयान की मांग करने के लिए बाध्य था,

**अभिनिर्धारित:** (सरकार और बचावत, जे.जे. द्वारा) अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर अपीलीय न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने का हकदार था कि जी न कि फिरोजपुर की फर्म इस निर्धारिती-फर्म में भागीदार थी [181 डी-ई]

**आयकर आयुक्त बनाम शिवकाशी मैच एक्सपोर्टिंग कं. [1964]8 एस.सी.आर. 18** अनुगमन किया ।

(ii) यह प्रश्न कि क्या जी के हिस्से के संबंध में फिरोजपुर फर्म के सदस्यों बीच कोई उप-साझेदारी थी तात्विक नहीं हैं। क्योंकि, यह मानते हुए कि कोई उप-साझेदारी नहीं थी, फिरोजपुर फर्म के सदस्य निर्धारिती- फर्म मे भागीदार नहीं बनी मात्र उस खंड के आधार पर जो केवल फिरोजपुर भागीदारों के आपसी संबंधों को विनियमित करता है और निर्धारिती-फर्म में जी के हिस्से के संबंध में उनके बीच एक साझेदारी बनाई। [ 183 बी-डी]

**आयकर आयुक्त बनाम बाग्यालक्ष्मी एंड कंपनी [1965]2 एस.सी.आर.**22 , अनुगमन किया।

(iii) यद्यपि विधि का प्रश्न अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न हुआ था किन्तु उक्त प्रश्न विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था और उसका उत्तर स्वयं स्पष्ट था अतः उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण को प्रश्न संदर्भित करने के लिए बाध्य नहीं था। [184 डी]

मुधोलकर, जे. द्वारा (असहमति):वर्तमान मामला में यह मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या मामले की परिस्थितियों में, निर्धारिती फर्म धारा 26 ए. के तहत

पंजीकृत किए जाने योग्य है? उक्त परिस्थिति के कानूनन प्रभाव का अन्वेषण एक कानून का सवाल है। अपीलीय सहायक आयुक्त और न्यायाधिकरण ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया था कि क्या पंजीकरण के आवेदन के संबंध में निर्धारिती-फर्म में भागीदारों की वास्तविक स्थिति दर्शाती है अपीलीय सहायक कमिश्नर का तर्क केवल उप-साझेदारी के मामले के लिए प्रासंगिक था, और न्यायाधिकरण ने केवल कुछ निर्णयों का उल्लेख किया और विभागीय अपील को खारिज कर दिया । अपीलीय सहायक आयोग एवं ट्रिब्यूनल ने आयकर अधिकारी द्वारा पाए गए प्रासंगिक तथ्य को नजरअंदाज करके निर्णय लिया गया था उक्त निष्कर्ष कानून की त्रुटि के कारण दूषित है फिरोजपुर फर्म का गठन कब किया गया इस संबंध में उच्च न्यायालय ने भी एकस्पष्ट त्रुटि की है था और उस त्रुटि के आधार पर आगे निर्धारिती-फर्म का फिरोजपुर फर्म के संबंध में उप-साझेदारी बाबत त्रुटि की थी । इसके अलावा **आयकर आयुक्त बनाम शिवकाशी मैच एक्सपोर्टिंग कं. [1954] 1 एस. सी. आर. 18 का** और **आयकर आयुक्त बनाम बाग्यालक्ष्मी एंड कंपनी [1965] 2 एस.सी. आर.22 का निर्णय इस मामले के तथ्यों के लिए** लागू नहीं होती है क्योंकि, उन मामलों में टिप्पणियाँ इस तथ्य पर आधारित हैं कि पंजीकरण की मांग करने वाले फर्म में एक व्यक्ति भागीदार के रूप में स्वीकार किया गया था, जबकि वर्तमान मामले में पंजीकरण की मांग करने वाले फर्म **का** एक भागीदार प्रतिनिधि के रूप भागीदार था । इस प्रकार तत्काल मामले में कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसका समाधान नहीं किया गया है। इसलिए, न्यायाधिकरण को प्रश्न भेजने हेतु उच्च न्यायालय को निर्देश देना चाहिए था। [188 एच; जी. 190 एचः 189 एच; 188 ए-बी; 192 बी-डी]

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील सं. 605 वर्ष 1963.

पंजाब उच्च न्यायालय के आय-कर प्रकरण संख्या 16 वर्ष 1956 के निर्णय और आदेश दिनांकित 24 जनवरी, 1961 से विशेष अनुमति द्वारा अपील ।

निरेन डे, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल, गोपाल सिंह और आर. एन. सचथी, अपीलार्थी के लिए।

बिशन नारायण, ओ. सी. माथुर और जे. बी. दादाचंजी, उत्तरदाता।

निर्णय सरकार और बचावत जे.जे. द्वारा दिया गया था जे. बचावत जे. मुधोलकर ने एक असहमतिपूर्ण राय दी।

बचावत, जे. आय-कर पंजाब के आयुक्त द्वारा 66(2) भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 के तहत प्रस्तुत आवेदन को पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के आदेश के विरूद्ध विशेष अनुमति द्वारा यह अपील। 5 दिसंबर, 1952 को साझेदारी के साधन के तहत गठित मेसर्स की फर्म चंदर भान हरभजन लाल (जिसे बाद में निर्धारिती फर्म के रूप में संदर्भित किया गया है) के 14 भागीदार ने 21 अप्रैल, 1953 को आय-कर अधिकारी, परियोजना मंडल, अंबाला को 26 ए भारतीय आय-कर अधिनियम के तहत फर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन किया। इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि फिरोजपोर्ट कि चंदर भान एंड कंपनी के नाम की एक और फर्म थी, (इसके बाद फिरोजपुर फर्म के रूप में संदर्भित) की जिसमें 8 भागीदार थे और जिसका गठन 14 जून, 1952 के एक विलेख के तहत किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया थाः

"यदि निष्पादकों में से कोई एक व्यवसाय में प्रवेश करता है व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सभी फर्म के भागीदार लाभ के हकदार होंगे और उस व्यावसायिक समझौते से उपार्जित नुकसान के लिए पहले बताए गए शेयरों के अनुरूप उत्तरदायी होंगे"

गोसाईं चंदर भान नामक व्यक्ति दोनों निर्धारिती फर्म और फिरोजपुर फर्म का भागीदार था । 26-ए, के तहत निर्धारिती फर्म के पंजीकरण के लिए प्रस्तुत

आवेदन से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही के दौरान उक्त फर्म के भागीदारों में से एक, हर्भजन लाल ने 30 जनवरी 1954 को कहा:

"एम हरभजन लाल पुत्र रूपार के श्री राम चंद घोषणा करता हूं कि फर्म मेसर्स चंदर भान **हरभजन** लाल में 14 भागीदार शामिल थे जैसा कि वापसी और साझेदारी विलेख में उल्लेख किया गया है। गोसाईन चंदर भान अपनी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं बल्कि फर्म मेसर्स गोसाईन चंदर भान और कंपनी फिरोजपुर जिसके लगभग छह भागीदार हैं की ओर से भागीदार थे। अन्य भागीदार अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भागीदार हैं।

ऐसा लगता है कि निर्धारिती फर्म के अन्य भागीदारों ने इसी तरह के बयान 27 फरवरी, 1954 को दिए थे।

निर्धारित फर्म की पूंजी की आपूर्ति गोसाईं चंदर भान द्वारा की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गोसाईं चंदर भान ने फिरोजपुर की फर्म से पूंजी ली थी, और यह राशि फिरोजपुर की फर्म में उनके खातों में एक वस्तु के रूप में दिखाई गई थी।

आय-कर अधिकारी के आदेश 27 फरवरी, 1954 के अनुसार 26-ए. के तहत आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि (1) 5 दिसंबर, 1952 के विलेख में निर्धारिती फर्म के गठन की तारीख निर्दिष्ट नहीं की गई थी (2) विलेख के कुछ पक्षकरों को फर्म के बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है तथा वास्तव में उक्त फर्म के भागीदार नहीं है और कर योग्य राशि को कम करने के उद्देश्य से फर्म में भागीदारों की संख्या कृत्रिम रूप से वृद्धि की गई थी; (3) फर्म वास्तविक नहीं थी, क्योंकि उसका कोई बैंकिंग खाता नहीं था, उसके पास आय-कर निकासी प्रमाण पत्र नहीं था। पी. डब्ल्यू. डी. को अपने संविधान को अधिसूचित नहीं किया, और पी. डब्ल्यू. डी द्वारा किया गया भुगतान हरभजन लाल के नाम से प्राप्त किया था। अपील में, आय-कर अधिकारी के इन सभी निष्कर्षों को अपीलीय सहायक

आयुक्त, अंबाला शाखा,ने अपास्त किया । अपीलीय सहायक आयुक्त के निर्णय की सूचिता को चुनौती नहीं दी गई।

आय-कर अधिकारी ने यह भी माना कि यद्यपि विलेख दिनांकित 5 दिसंबर, 1952 के तहत गोसाईन चंदर भान का 6/16 वां हिस्सा था किन्तु वास्तव में फिरोजपुर फर्म निर्धारिती फर्म की भागीदार थी जिसमें उसका 6/16 वां हिस्सा था और इसके परिणामस्वरूप, निर्धारिती फर्म का गठन अवैध रूप से किया गया था, क्योंकि(1) फिरोजपुर फर्म कानूनी रूप से निर्धारिती फर्म में भागीदार नहीं हो सकती थी।; (2) निर्धारिती फर्म के भागीदारों की कुल संख्या 21 थी और(3) इसके अलावा, फिरोजपुर फर्म के आठ भागीदारों के व्यक्तिगत शेयरों को विलेख दिनांक 5 दिसंबर, 1952 में निर्दिष्ट नहीं किया गया था। इन निष्कर्षों पर, आयकर अधिकारी ने धारा 26-ए के तहत आवेदन को खारिज कर दिया। अपील **में**, अपीलीय सहायक आयुक्त ने इन निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया और कहा कि गोसाईं चंदर भान अपनी व्यक्तिगत क्षमता में निर्धारिती फर्म के भागीदार थे, न कि फिरोजपुर फर्म के सभी भागीदारों के प्रतिनिधि के रूप में और उनकी ओर से। उनका मानना था कि गोसाईं चंदर भान ने केवल फिरोज पोर फर्म के अन्य भागीदारों के साथ निर्धारिती फर्म में अपने लाभ और हानि को साझा करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस तरह के समझौते ने फर्म के दूसरे भागीदारों को, निर्धारिती फर्म में भागीदार नहीं बनाया, और समझौते का प्रभाव केवल एक उप-साझेदारी का गठन करना था। उस पर आगे की अपील, में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली शाखा ने अपीलीय सहायक आयुक्त के इन निष्कर्षों को बरकरार रखा और अभिनिर्धारित किया कि उन निष्कर्षों का समर्थन आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स अगरडीह कोलियरी (1) और आय आयुक्त-कर v. लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी (2) के निर्णयों द्वारा किया गया था। आय-कर आयुक्त, पंजाब ने तब 66(1) भारतीय आय-

कर अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण में निम्नलिखित प्रश्नों को उच्च न्यायालय को भेजने के लिए आवेदन किया।

" 1. क्या आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स अगरडीह कोलियरी कंपनी के मामले में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आयकर आयुक्त बनाम लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी के मामले में पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय को इस मामले में लागू करने में सही था

2. यदि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सकारात्मक है। क्या ऊपर उल्लिखित निर्णय एक सही कानून निर्धारित करते हैं।

3. क्या यह दिखाने के लिए कोई सामग्री है कि गोसाईं चंदर भान द्वारा फिरोजपुर में अन्य व्यक्तियों के साथ एक उप-साझेदारी बनाई गई थी।

4. मामले की परिस्थितियों में निर्धारिती की सही स्थिति फर्म या व्यक्तियों का संगठन थी और क्या इस मामले में भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 26-ए के तहत पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है।

न्यायाधिकरण ने अपने आदेश 5 सितंबर, 1955 के द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि प्रश्नों को न्यायिक निर्णयों द्वारा समाप्त किया गया था और उन्हें फिर से उच्च न्यायालय में भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। 18 सितंबर, 1956 को आयकर आयुक्त ने पंजाब उच्च न्यायालय में 66(2) भारतीय आय-कर अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण को उपरोक्त प्रश्नों को सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय को भेजने हेतु निर्देशित किए जाने बाबत आवेदन किया। - उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन पर, सुनवाई के समय आय-कर आयुक्त के वकील ने प्रश्न संख्या 4 और 2 छोड़ दी और निम्नलिखित दो कानून के प्रश्न निर्णय के लिए प्रस्तुत किया

"(क) क्या अभिलेख पर इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री है कि गोसाईं चंदर भान **वास्तविकता में** निर्धारिती फर्म का भागीदार थे और गोसाईं चंदर भान एंड कंपनी ऑफ फिरोजपुर के सभी भागीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिनिधि क्षमता में भागीदार नहीं है, और(ख) क्या वर्तमान उप-साझेदारी के मामले पर न्यायाधिकरण द्वारा आदेश में निर्दिष्ट दो मामले लागू होते हैं?"

24 जनवरी, 1961 के अपने आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि कानून के प्रश्न हल हो गए हैं। आय-कर आयुक्त अब विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में अपील करते हैं।"

अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया कि फिरोजपुर फर्म के सभी भागीदार निर्धारिती फर्म में भागीदार थी, (1) तथ्य के संबंध में निर्धारिती फर्म की पूंजी फिरोजपुर फर्म से गोसाईन चंदर भान द्वारा सुरक्षित, कि थी (2)साझेदारी विलेख 14 जून, 1952 के खंड तहत फिरोजपुर फर्म के सभी भागीदार गोसाईन चंदर भान के निर्धारिती फर्म में लाभ और हानि के हिस्से के संबंध में लिए हकदार एवं उत्तरदायी थे, और (3) हरभजन लाल और निर्धारिती फर्म के अन्य भागीदार का बयान कि गोसाईं चंदर भान निर्धारिती फर्म में व्यक्तिगत हैसियत से भागीदार नहीं था बल्कि फिरोजपुर फर्म की ओर से भागीदार थे। इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है। हमारे सामने असली सवाल यह है कि क्या न्यायाधिकरण के आदेश से कानून का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है । हमें लगता है कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। दिनांक 5 दिसंबर, 1952 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि गोसाईं चंदर भान और विलेख के 13 अन्य पक्षकार निर्धारिती फर्म के भागीदार थे। विलेख के प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत नहीं होता है कि गोसाईन चंदर भान फिरोजपुर फर्म के प्रतिनिधि के रूप में निर्धारिती फर्म में भागीदार थे या कि फिरोजपुर फर्म निर्धारिती फर्म में भागीदार थे । अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर,

अपीलीय न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने का हकदार था  कि फिरोजपुर फर्म नहीं बल्कि गोसाईन चंदर भान निर्धारिती फर्म में भागीदार थे ।

निर्धारिती फर्म की पूंजी की आपूर्ति गोसाईं चंदर भान द्वारा की गई थी। गोसाईं चंदर भान ने अपनी ओर से फिरोजपुर की फर्म से पूंजी की राशि ली थी, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अलावा अन्य तरीके से पैसा लिया था। साझेदारी विलेख का खंड फिरोजपुर फर्म को इस प्रभाव के लिए बाध्य करता है कि फिरोजपुर फर्म के सभी भागीदार गोसाईन चंदर भान के के संबंध में निर्धारिती फर्म में लाभ के हकदार हैं और हानि के लिए उत्तरदायी हैं ये दर्शित करने के गोसाईन चंदर भान के निर्धारिती फर्म के लाभ और हानि में हिस्से के संबंध में गोसाईन चंदर भान और फिरोजपुर फर्म के अन्य भागीदारों के बीच साझेदारी है। फिरोजपुर फर्म के सदस्यों के बीच की साझेदारी, यदि कोई हो, तो फिरोजपुर फर्म को निर्धारिती फर्म में भागीदार नहीं बनाती है। फिरोजपुर फर्म निर्धारिती फर्म का गठन करने वाले साझेदारी समझौते का पक्षकार नहीं है। गोसाईं चंदर भान अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कानूनी रूप से निर्धारिती फर्म में भागीदार हो सकते हैं, और यह तथ्य कि उन्होंने फिरोजपुर फर्म से पूंजी हासिल की थी, या कि उन्होंने निर्धारिती फर्म में अपने हिस्से के संबंध में फिरोजपुर फर्म के अन्य सदस्यों के साथ साझेदारी की थी, यह नहीं दर्शाता है कि फिरोजपुर फर्म निर्धारिती फर्म का एक हिस्सा है, या यह कि निर्धारिती फर्म वैध रूप से गठित नहीं की गई हो । आयकर आयुक्त बनाम शिवकाशी मैच निर्यातक कंपनी (1), जे. सुब्बा राव ने कहाः

"किसी फर्म का भागीदार निश्चित रूप से अपनी पूंजी सुरक्षित कर सकता है। किसी भी स्रोत से या अपने लाभ को अपने उप-भागीदार को या कोई अन्य व्यक्ति को सौंप दें। । इन तथ्यों के आधार पर एक वैध साझेदारी को फर्जी में परिवर्तित करने की कल्पना नहीं की जा सकती।"

हरभजन लाल और  निर्धारिती फर्म के अन्य सहयोगियों के बयान इस मामले को आगे नहीं ले जाती है। 30 जनवरी, 1954 के बयान में  हरभजन लाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्धारिती फर्म **के** विलेख 5 दिसंबर, 1952 में उल्लिखित 14 भागीदार निर्धारिती फर्म शामिल थे। यह सच है कि उन्होंने कहा कि गोसाईन चंदर भान व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि  फिरोजपुर फर्म की ओर से भागीदार थे लेकिन यह बयान फिरोजपुर फर्म का गठन करने वाला भागीदार विलेख **के** खंड की पृष्ठभूमि में पढ़ा जाना चाहिए जिसके तहत गोसाई चंदर भान के निर्धारिती फर्म में लाभ एवं  नुकसान के  हिस्से में भागीदार थे  निष्पक्ष रूप से पढ़े गए बयान से पता चलता है कि केवल 5 दिसंबर, 1952 के विलेख में उल्लिखित 14 व्यक्ति निर्धारिती फर्म के हिस्सेदार थे। अगर फिरोजपुर फर्म के 8 भागीदार भी निर्धारिती फर्म में भागीदार थे तो, हर्भजन लाल ने यह नहीं **कहता** कि निर्धारिती फर्म के भागीदारों की संख्या केवल 14 थी।

अपीलार्थी के वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय ने गलती से यह मान कि फिरोजपुर फर्म का गठन करने वाले साझेदारी विलेख की तारीख 14 जून, 1954 हो, जबकि वास्तव में यह साझेदारी की तारीख 14 जून, 1952 थी। अपीलार्थी के लिए वकील सही ढंग से इंगित किया कि यह  गलत धारणा की गई की  फिरोजपुर फर्म का गठन करने वाले साझेदारी विलेख को 5 दिसंबर, 1952 को निष्पादित किया गया था  जब निर्धारिती फर्म का गठन किया गया था , तब उच्च न्यायालय ने माना कि चंदर भान गोसाईं और फिरोजपुर फर्म में अन्य भागीदार के बीच चंदर भान गोसाई के निर्धारिती फर्म में  हिस्से बाबत एक उप-साझेदारी थी वकील ने तब तर्क दिया कि कानून में, साझेदारी के गठन के बाद ही एक उप-साझेदारी प्रवेश किया जाता है और इसलिए, गोसाईन चंदर भान के निर्धारिती फर्म में हिस्से के संबंध फिरोज के सदस्यों के बीच कोई उप-साझेदारी

नहीं थी । इस तर्क के समर्थन वकील ने साझेदारी पर **लिंडले में 12 वीं संस्करण, पीपी 99-100** भरोसा किया:

"एक उप-साझेदारी जैसा कि पहले थी, एक साझेदारी के भीतर एक साझेदारी है।; यह एक भागीदार के अस्तित्व का अनुमान लगाता है जिसके वह स्वयं अधीनस्थ है।"

हमने वकील की इस धारणा की शुद्धता की जांच नहीं की कि यह अनुच्छेद इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि प्रमुख साझेदारी के अस्तित्व में आने की प्रत्याशा में उप-साझेदारी का समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन यह प्रश्न कि क्या 14 जून, 1952 के विलेख में प्रासंगिक खंड ने निर्धारिती फर्म में चंदर भान के हिस्से के संबंध में एक उप साझेदारी का निर्माण किया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह विलेख निर्धारिती फर्म के गठन से पहले निष्पादित किया गया था, मामले के उद्देश्य के लिए सामग्री नहीं है, और इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। इस खंड में फिरोजपुर फर्म के भागीदारों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया हैऔर निर्धारिती फर्म में गोसाई चंदर भान के हिस्से के संबंध में उनके बीच एक साझेदारी बनाई। मान लीजिए, बिना यह तय किए कि यह साझेदारी, वास्तव में, एक उप साझेदारी नहीं थी से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि फिरोजपुर फर्म के भागीदारों निर्धारिती फर्म में भागीदार बन गई। इस खंड के कारण विज़-ए-विज़ फिरोजपुर फर्म के भागीदार, गोसाईन चंदर भान को निर्धारिती फर्म में उनके प्रतिनिधि के रूप में नामांकित किया जा सकता है;फिर भी, वे निर्धारिती फर्म का गठन करने वाले साझेदारी अनुबंध के लिए अजनबी थे और उसमें भागीदार नहीं बन जाते हैं । **आयुक्त आयकर बनाम बाग्यालक्ष्मी एंड कंपनी** (1), सुब्बाराव, जे. ने कहाः

"साझेदारी के अनुबंध का कोई संबंध दूसरों के प्रति साझेदारी में लाभ के शेयर करने के संबंध में भागीदारों का दायित्व नहीं है। यह केवल विनियमित

करता हैभागीदारों के अधिकार और देनदारियाँ। एक साथी  एक संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता; वह एक ट्रस्टी हो सकता है; वह दूसरों के साथ उप-साझेदारी कर सकता है; वह कर सकता है एक समझौते के तहत, व्यक्त या निहित, प्रतिनिधि बनें व्यक्तियों के एक समूह का संवेदनशील; वह एक बेनामीदार हो सकता है। ऐसे सभी मामलों में वह दोहरी स्थिति में रहता है। साझेदारी के लिए, वह अपने व्यक्तिगत रूप में कार्य करता हैं;  तीसरे पक्षके लिए, अपने प्रतिनिधि रूप में कार्य करता हैं। तीसरे पक्ष, जिनका भागीदारों में से एक प्रतिनिधित्व करता है , दूसरे भाग के खिलाफ अपने अधिकारों को लागू नहीं कर सकते हैं  और न ही अन्य भागीदार उक्त के खिलाफ ऐसा कर सकते हैं  तीसरे पक्ष। उनका अधिकार समझौते की शर्तें अनुसार केवल उनके साथी-प्रतिनिधि के लाभ में एक हिस्से का है।"

स्पष्ट रूप से, 14 जून के विलेख में प्रासंगिक खंड, निर्धारिती फर्म का गठन, करने वाले  साझेदारी समझौते 5 दिसंबर 1952 का हिस्सा नहीं था और एस 26 - ए.के तहत निर्धारिती फर्म के भागीदारों का पंजीकरण का दावा करने का अधिकार प्रभावित नहीं किया यह कहना संभव नहीं है कि रिकॉर्ड पर इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि गोसैन चंदर भान अपनी व्यक्तिगत क्षमता में निर्धारिती फर्म के भागीदार थे, न कि फिरोजपुर फर्म का प्रतिनिधित्व करने के रूप में। सवाल यह हैं कि क्या गोसाईं चंदर के हिस्से के संबंध में फिरोजपुर फर्म सदस्यों के बीच कोई उप-साझेदारी थी यह तात्विक नहीं है क्योंकि यह मानते भी लिया जावे कि कोई उप साझेदारी नहीं थी किन्तु 14 जून, 1952 या अन्यथा दिनांकित विलेख में संबंधित खंड के आधार पर फिरोजपुर फर्म के सदस्य निर्धारिती फर्म में भागीदार नहीं बने। इसलिए हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण के इस आदेश से कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं उठता है।

अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण के आदेश से कानून का प्रश्न उत्पन्न होने के कारण, उच्च न्यायालय मामले के बयान को बुलाने के लिए बाध्य था। हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। जहां, जैसा कि इस मामले में, कानून का प्रश्न अस्थाई नहीं है और प्रश्न का उत्तर स्वयं स्पष्ट है, उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण से प्रश्न को संदर्भित करने की अपेक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है।हमारी राय में, उच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए एस 66 (2)के तहत अपीलार्थी के आवेदन को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया।

नतीजतन, अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

**मुधोलकर, जे.** यह पंजाब के उच्च न्यायालय के एक फैसले की अपील है जिसमें आयुक्त द्वारा 66(2) भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण से कानून के कुछ प्रश्नों को उच्च न्यायालय को भेजने का आह्वान करने के लिए प्रस्तुत की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है।

प्रासंगिक तथ्य ये हैंः

29 दिसंबर, 1948 को गोसाईन चंदर भान और चार अन्य लोगों ने "गोसाईन चंदर भान एंड कंपनी" के नाम से कॉन्ट्रैक्टटोरों का व्यवसाय चलाने के लिए साझेदारी की। साझेदारी फिरोजपुर में की गई थी और गोसाईन चंदर भान फर्म में एक प्रमुख शेयरधारक थे। 14 जून, 1952 के साझेदारी विलेख द्वारा फर्म का पुनः गठन किया गया और तीन अन्य व्यक्तियों जी को उसमें भागीदार के रूप में भर्ती किया गया। हालाँकि, पुराना नाम जारी रहा। साझेदारी की शर्तों में से एक यह थी कि यदि किसी भी भागीदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ आंशिक रूप से कोई काम किया जाता है, तो उस काम से होने वाले लाभ और हानि को फर्म में उनके शेयरों के अनुपात में सभी भागीदारों के बीच विभाजित किया जाएगा। 5 दिसंबर, 1952 को मेसर्स नाम की एक साझेदारी फर्म। रूपार में

'चंदर भान हर्भजन लाल' का गठन किया गया था। साझेदारी का नाम मेसर्स चंदर भान **हरभजन** लाल रूपर में किया गया गोसाईं चंदर भान सहित 14 व्यक्तियों का भागीदार के रूप में और फर्म का उद्देश्य गोसाईं चंदर भान एंड कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय के समान व्यवसाय करना था। उल्लेखनीय है कि इस फर्म में भी गोसाईन चंदर भान प्रमुख शेयरधारक थे। सुविधा के लिए हम 14 जून, 1952 को गठित फर्म को फिरोजपुर और दिसंबर 5,1952 में गठित रूपर फर्म के रूप में बुलाएंगे।

21 अप्रैल, 1953 को आयकर अधिकारी, अंबाला के समक्ष रूपर फर्म के भागीदारों द्वारा निर्धारण वर्ष 1953-54 के लिए अधिनियम का 26 - ए के तहत फर्म के पंजीकरण के लिए एक आवेदन साझेदारी के विलेख 5 दिसंबर, 1952 के साथ प्रस्तुत किया गया था। आय-कर अधिकारी ने फर्म को बदनाम करने वाले भागीदारों की जांच की और फर्म के गठन के संबंध में सही स्थिति का पता लगाने के लिए उनके बयान दर्ज किए। हर्भजन लाल ने 30 जनवरी, 1954 के अपने बयान में और अन्य भागीदारों ने 27 फरवरी, 1954 के अपने बयानों में स्वीकार किया कि गोसाईं चंदर भान ने भागीदार जहाज में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं बल्कि फिरोजपुर फर्म की ओर से प्रवेश किया था। आयकर अधिकारी ने यह भी पाया कि गोसाईं चंदर भान के नाम पर रूपर फर्म में निवेश किया गया धन भी फिरोजपुर फर्म द्वारा प्रदान किया गया। इन पर और कुछ अन्य तथ्यों के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 5 दिसंबर, 1952 के साझेदारी विलेख में फर्म के वास्तविक भागीदारों को निर्दिष्ट नहीं किया गया था और इसलिए, फर्म को पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। वह आगे आया कि वास्तव में फिरोजपुर के सभी भागीदार अकेले गोसाईन चंदर भान नहीं, बल्कि फर्म भी रूपर फर्म में 13 अन्य व्यक्तियों के साथ भागीदार थे, पार्टनर्स की कुल संख्या 20 से अधिक थी। ऐसी साझेदारी कानून में अमान्य होने के कारण फर्म को 26 ए अधिनियम के तहत

पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने 27 फरवरी, 1954 के अपने आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया। हालाँकि, अपील में उनके आदेश को अपीलीय आयोग द्वारा 12 अगस्त, 1954 को उलट दिया गया था।आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (दिल्ली शाखा) के समक्ष आयकर अधिकारी द्वारा की गई अपील को उसके द्वारा 5 सितंबर, 1955 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। ऐसा करने में न्यायाधिकरण ने खुद को आय आयुक्त-कर बनाम में निर्णयों पर आधारित किया। अगरडीह कोलियरी कंपनी (1) और आयकर आयुक्त v. लक्ष्मी ट्रेडिंग कं. (2) आय-कर आयुक्त ने तब एस के तहत न्यायाधिकरण में आवेदन किया। 66 (1) कानून के चार प्रश्नों को उच्च न्यायालय को संदर्भित करना। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने 5 मार्च, 1956 को आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद आयुक्त एस 66 (2) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका को प्राथमिकता दी। को कानून के चार प्रश्नों को उसके पास भेजने का निर्देश देना। हालाँकि, सुनवाई में केवल निम्नलिखित दो प्रश्न पूछे गए थे। उनकी तरफ सेः

"(1) क्या अभिलेख पर कोई सामग्री है इस निष्कर्ष का समर्थन करें कि गोसाईन चंदर भान थे निर्धारिती फर्म का वास्तविक भागीदार और इसमें भागीदार नहीं था सभी भागीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिनिधि क्षमता गोसाईन चंदर भान एंड कंपनी ऑफ फिरोजपुर?

(2) क्या वर्तमान उप-साझेदारी का मामला है जिन दो मामलों में ए. आई. आर. 1935 पटना 225 और (1953) 24 न्यायाधिकरण के आदेश में निर्दिष्ट आई. टी. आर. 173 आवेदन करें?"

उच्च न्यायालय, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, ने आवेदन को खारिज कर दिया और अब यह मामला विशेष अवकाश द्वारा हमारे सामने है।

हमारे सामने उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, विभाग के लिए, निम्नलिखित दो बिंदु उठाए गए हैंः

(1) कि कानून का सवाल था जो  उच्च न्यायालय को संदर्भित करने के लिए न्यायाधिकरण का दायित्व था;

(2) कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों पक्षकार **ने** गलत परिसरों में कानून के सवाल का फैसला  किया ।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर के अनुसार कानून का सवाल जनरल, हैः " चाहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर फर्म चंदर भान हर्भजन लाल एस 26ए के तहत पंजीकृत था।  यह ध्यान में रखना चाहिए कि सवाल यह नहीं है कि क्या अभिलेख पर ऐसी सामग्री थी जिसके आधार पर न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि फर्म पंजीकृत थी लेकिन क्या, तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि यह पंजीकरण योग्य था। दूसरे शब्दों में,सवाल यह है कि सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव क्या है?और यह नहीं कि केवल कुछ तथ्यों का क्या प्रभाव पड़ता है। विद्वान अपर महान्यायवादी का तर्क है कि जब कहा जाता है कि कानून का सवाल उठता है उच्च न्यायालय रिफेन्स को बुलाने के लिए बाध्य है और यह महत्वहीन है कि प्रश्न का निपटारा पहले से ही किया गया है ।

यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एस 66(1) के तहत।  न्यायाधिकरण मामले का एक बयान तैयार करने और सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य है उच्च न्यायालय को। न्यायाधिकरण के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। जहाँ, तथापि, न्यायाधिकरण ऐसा करने से इनकार करता है और उच्च न्यायालय को 66(2) अधिनियम के तहत स्थानांतरित किया जाता है। धारा 66(2) उच्च न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करती है और यदि उच्च न्यायालय की राय है कि यद्यपि कानून का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है या यह कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है तो वह याचिका को अस्वीकार कर सकता है। इसलिए, हमें यह पता लगाना है कि क्या इस मामले में कानून का कोई सवाल पैदा होता है और यदि

ऐसा है तो क्या यह कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल है। यह पता लगाने के लिए कि क्या कानून का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, उन तथ्यों का पता लगाना आवश्यक है जो आय-कर लेखकों द्वारा स्थापित किए गए हैं। मैं आयकर विभाग द्वारा पाए गए तथ्यों को दोहराऊंगा।

(1) मूल फर्म गोसाईन चंदर भान एंड कंपनी थी जिसका 29 दिसंबर, 1948 को फिरोजपुर में इसका गठन किया गया।

(2) इसमें गोसाईन चंदर भान की बड़ी हिस्सेदारी थी।

(3) इस फर्म को भंग कर दिया गया और जून 14 , 1952 .में इसका पुनर्गठन किया गया।

(4) मूल फर्म में केवल 5 भागीदार थे। रिकॉन में गोसाईं चंदर भान सहित प्रतिष्ठित फर्म में गोसाईं सहित 8 भागीदार थे। चंदर भान।

(5) पुनर्गठित साझेदारी में सबसे बड़ा हिस्सा यह गोसाईं चंदर भान की थी।

(6) 5 दिसंबर 1952 का साझेदारी विलेख निर्दिष्ट किया गया था। गोसाईं चंदर सहित 14 लोगों के नाम भान ने भागीदार के रूप में लेकिन नाम निर्दिष्ट नहीं किए गोसाईन चंदर भान एंड कंपनी के सभी भागीदार फिरोजपुर।

(7) गोसाईं चंदर भान द्वारा निवेशित धन रुपार फर्म से संबंधित निधियों से बाहर आया फिरोजपुर की कंपनी।

(8) हर्भजन लाल और रूपर फर्म के अन्य साझेदार स्वीकार किया कि गोसाईन चंदर भान इसका हिस्सा नहीं थे रूपर फर्म में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लेकिन फिरोजपुर फर्म की ओर से इसमें शामिल हुए थे।

(9) रूपर फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय समान है। जिसे फिरोजपुर फर्म द्वारा चलाया जाता था।

उक्त तथ्य के प्रश्नों पर इनमें से किसी भी निष्कर्ष को अपीलीय सहायक आयुक्त या ट्रिब्यूनल द्वारा नकार या परेशान नहीं किया गया है। इसलिए, इन निष्कर्षों को यह पता लगाने के लिए आधार के रूप में लिया जाना चाहिए कि क्या कानून का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, और यदि ऐसा होता है तो प्रश्न का निर्णय लेने के लिए उन्हें ध्यान में रखना होगा। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह कहते हुए एक गंभीर गलती की कि फिर से गठित फिरोजपुर साझेदारी का गठन 14 जून, 1954 को किया गया था, जो कि रूपर साझेदारी के गठन के बाद हुआ था। यह त्रुटि स्पष्ट रूप से हुई है यह एक और गलती है, यानी इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कि फिरोजपुर साझेदारी रूपर साझेदारी के संबंध में एक उप-साझेदारी थी। अब, आम तौर पर एक उप-भागीदार जहाज तभी हो सकता है जब पहले से ही एक और साझेदारी मौजूद हो। चूंकि वास्तव में रूपर साझेदारी फिरोजपुर साझेदारी के गठन के बाद अस्तित्व में आई थी, इसलिए बाद वाला पहले वाले के संबंध में एक उप-साझेदारी के रूप में खड़ा नहीं हो सकता है। जैसा कि लिंडले ऑन पार्टनरशिप में पी. 99 यह हैः

" एक उप-साझेदारी जैसा कि था, साझेदारी में एक साझेदारी हैः यह एक भाग के अस्तित्व का अनुमान लगाता है जिसके लिए वह स्वयं अधीनस्थ है "।

कानून के इस कथन की शुद्धता पर हमारे सामने किसी भी पक्ष द्वारा तर्क नहीं किया गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह स्थापित कानून है कि जहां किसी फर्म के विनियमन के लिए आवेदन एस की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। 26-ए और नियमों में से और यह पाया जाता है कि साझेदारी वास्तविक नहीं है-आयकर अधिकारी फर्म को पंजीकरण के लिए स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि क्या कानून की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई फर्म वास्तविक है या फर्जी है

या इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, आयकर अधिकारी को साझेदारी के विलेख तक ही सीमित रहना चाहिए। उसके पास भागीदारों की जाँच करने की शक्ति है और उन्हें फर्म की वास्तविक गलतियों के बारे में या अन्यथा खुद को संतुष्ट करने के लिए और कानून की आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए सबूत पेश करने की आवश्यकता है। हालाँकि, अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश के पैराग्राफ 2 और 3 से पता चलता है कि उन्होंने 5 दिसंबर, 1952 के साझेदारी विलेख में पाठ को इस सवाल का निर्णायक माना है कि रूपर फर्म में वास्तविक भागीदार कौन थे। मुझे आयकर अधिकारी के निष्कर्षों पर कोई चर्चा या संदर्भ भी नहीं मिल रहा है, जिन्हें मैंने पहले संक्षेप में प्रस्तुत किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पैराग्राफ 4 में उन्होंने आय-कर अधिकारी द्वारा पाए गए कुछ तथ्यों और उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का उल्लेख किया और उन्हें खारिज कर दिया। उन तथ्यों को ध्यान से बाहर रखते हुए अन्य तथ्य भी हैं जो विचार के लिए प्रासंगिक हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय सहायक आयुक्त ने उनकी अनदेखी की है। उन तथ्यों के कानूनी प्रभाव की पुष्टि करना मेरे निर्णय में एक सवाल होगा कानून। हमारे समक्ष यह विवादित नहीं है कि रजिस्ट्रा के लिए आवेदन उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्धारित करने चाहिए जो फर्म के वास्तविक भागीदार हैं और इसलिए यह पता लगाना आयकर अधिकारियों का दायित्व है कि क्या अपनी व्यक्तिगत क्षमता में या व्यक्तियों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने के रूप में साझेदारी में शामिल हुए। यदि दूसरे पक्ष की जानकारी के अनुसार वह व्यक्तियों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वे किसी अन्य साझेदारी के सदस्य हों या एक संयुक्त हिंदू परिवार के, तो यह निर्णय के लिए एक सवाल होगा कि क्या वे सभी व्यक्ति इस तरह से भागीदार बन गए हैं और यह कानून का सवाल होगा। अपने आदेश के पैराग्राफ 6 में ऐसा लगता है कि

अपीलीय सहायक आयुक्त के दिमाग में यह था और पैराग्राफ के प्रासंगिक हिस्से को उद्धृत करना उपयोगी होगाः

" ऐसा करने से पहले दो आवश्यक शर्तें हैं  जिनकी पूर्ति पर कहा जा सकता है कि  भागीदारों के बीच जो संविदात्मक संबंध लाया गया है संबंध है एक साझेदारी और दो शर्तें हैं कि भाग उद्यमियों को व्यवसाय के लाभ को साझा करने के लिए सहमत होना चाहिए और व्यवसाय उन सभी या उनमें से किसी एक द्वारा उन सभी के लिए।चलाया जाना चाहिए।  कानून में साझेदारी की शर्त यह हो सकती है कि  एक प्रमुख फर्म में भागीदार और एक अन्य व्यक्ति प्रमुख फर्म में भागीदार के हिस्से के संबंध में उप-फर्म में भागीदारों को आवेदन करने का अधिकार देने के लिए धारा 26-ए के तहत उसका पंजीकरण भागीदार और उनमें से एक लाभ साझा करने के लिए सहमत होता है एक अजनबी के साथ उसके द्वारा व्युत्पन्न, यह समझौता  अजनबी को मूल फर्म में भागीदार नहीं बनाते है। इस तरह के समझौते का परिणाम एक उप-भाग का गठन करना है।  यह अपने पक्षों को आपस में भागीदार बनाता है। यह प्रधान फर्म के अन्य सदस्यों को प्रभावित नहीं करता है।

अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा यह मानने के लिए एकमात्र यह आधार दिया गया कि गोसाईन चंदर भान अपनी व्यक्तिगत क्षमता में रूपर फर्म में भागीदार थे, साझेदारी विलेख की प्रस्तावना 'स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि अनुबंध करने वाले पक्ष 14 थे और गोसाईन चंदर भान अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एक भागीदार थे।' यह सच है कि उन्होंने अपने निष्कर्ष के समर्थन में आयकर अधिकारी द्वारा दिए गए कुछ आधारों को खारिज कर दिया है, लेकिन जैसा कि पहले ही कहा गया है, उन्होंने आयकर अधिकारी द्वारा पाए गए अन्य तथ्यों पर विचार करने में पूरी तरह से चूक की है जो सीधे इस मुद्दे पर हैं। ऐसा हो सकता है कि निष्कर्ष को बिना किसी सबूत के आधारित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी, जैसा

कि प्रासंगिक तथ्यों की अनदेखी करके यह निष्कर्ष निकाला गया है, यह कानून की त्रुटि से दूषित हो जाता है।

ऊपर उद्धृत अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश के पैरा 6 का पहला वाक्य एस. 4 साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते है और अप्राप्य है। बाकी सब ऐसा प्रतीत होता है कि  आय-कर आयुक्त, पंजाब बनाम लक्ष्मी। ट्रेडिंग कंपनी (1) में  निर्णय के मुख्य नोट **को** उद्धरण किया है। । वह प्रश्न जो निर्णय के लिए सामने आया कि

"क्या कानून में  एक प्रमुख फर्म में एक भागीदार और एक अन्य व्यक्ति प्रमुख फर्म में भागीदार के हिस्से के संबंध में साझेदारी की शर्त हो सकती है ताकि उप-फर्म में भागीदारों को धारा 26-ए आय-कर अधिनियम 1922 के तहत आवेदन करने का अधिकार है?

और इसका जवाब हां में दिया गया।"

एक उप-साझेदारी भी हो सकती है, जैसा कि विद्वान अपीलीय द्वारा कहा गया है। सहायक आयुक्त, एस के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करें। 26-ए. लेकिन यह सब कहाँ ले जाता है? यहां जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या प्रमुख फर्म ने दूसरे के साथ साझेदारी की है या क्या मुख्य फर्म के भागीदारों में से केवल एक ने दूसरे के साथ साझेदारी की है। क्योंकि वास्तव में यही सवाल है। अपीलार्थी के अनुसार, एक फर्म के रूप में फिरोजपुर फर्म केवल गोसाईन चंदर भान में ही नहीं, बल्कि रूपर फर्म में भी भागीदार बन गई है। विद्वत अपीलीय सहायक आयुक्त ने मामले के इस पहलू पर खुद को संबोधित नहीं किया है। पैराग्राफ के अंत में विद्वान अपीलीय सहायक आयुक्त ने कहा हैः अभिलेख पर ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो आयकर अधिकारी के इस निष्कर्ष को पुष्ट करे कि उनके द्वारा की गई स्थानीय पूछताछ को देखते हुए फर्म वास्तविक नहीं थी। हालाँकि, यह पूरा सवाल नहीं है। इस मामले में जो पूरा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या इस मामले के तथ्यों

और परिस्थितियों में फर्म चंदर भान हरभजन लाल एस के तहत पंजीकृत थी। 26-ए, परिस्थितियां यह थीं कि किसी अन्य और पहले से मौजूद फर्म का एक भागीदार उस अन्य फर्म के भागीदारों की ओर से चंदर भान हरभजन लाल में भागीदार बन गया था, कि वह उस फर्म से संबंधित धन लाया था और नई फर्म को उसी तरह का व्यवसाय करना था जैसा पुरानी फर्म कर रही थी। इसके अलावा, अपीलीय सहायक आयुक्त का तर्क केवल उप-साझेदारी के मामले के लिए प्रासंगिक होगा। इसे कुछ अलग तरीके से कहने के लिए सवाल यह है कि क्या पंजीकरण के लिए आवेदन रूपर फर्म में वास्तविक भागीदारों के संबंध में वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। अपील में सहायक आयुक्त या न्यायाधिकरण द्वारा भी इस पर विचार नहीं किया गया है।

न्यायाधिकरण ने केवल लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी का मामला (1) और अगरडीह कोलियरी कंपनी का मामला के फैसलों का उल्लेख किया और विभाग की अपील को खारिज कर दिया। उत्तरार्द्ध भी उप-साझेदारी का मामला है और यह हस्तगत मामले को तय करने में हमारी सहायता नहीं करता है।

उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि जो प्रश्न यहाँ उत्पन्न हुआ है उसका इस न्यायालय के तीन निर्णयों द्वारा पहले ही निपटाए जा चुके हैं। इनमें से पहला आयकर आयुक्त मद्रास बनाम. शिवकाशी मैच एक्सपोर्टिंग कंपनी, शिवकाशी(3)। उस मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केवल यह तथ्य कि पंजीकरण की मांग करने वाले फर्म के भागीदारों में से एक ने अपनी पूंजी दूसरे फर्म से लाई थी जिस फर्म में वह भागीदारों में से एक थे और इस बात का रुख कि उन्होंने पूर्व फर्म से प्राप्त लाभ को बाद की फर्म में अपने भागीदारों के साथ साझा किया, पूर्व साझेदारी को फर्जी नहीं बना दिया। सबसे पहले यह परिस्थिति कि तथ्यों के एक निश्चित समूह के आधार पर यह न्यायालय किसी विशेष निर्णय पर पहुंचा है, आवश्यक रूप से इसे एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती नहीं

बनाएगा, भले ही उस न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष जिस पर उसका निर्णय आधारित हो। दूसरे स्थान पर हमारे पास यह तथ्य है कि पंजीकरण की मांग करने वाले फर्म के भागीदारों में से एक अपनी प्रतिनिधि क्षमता में एक भागीदार था, न कि केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एक भागीदार। अगला मामला जिस पर भरोसा किया गया है वह है कमिश्नर ऑफ आय-कर, अहमदाबाद बनाम। अब्दुल रहीम एंड कंपनी (1) उस मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह परिस्थिति कि भागीदारों में से एक दूसरे के लिए बेनामीदार था, एस 26-ए के तहत पंजीकृत करने से इनकार करने को उचित नहीं ठहराता है और आवश्यक शर्तों को दोहराया जो पंजीकरण की मांग करने वाली फर्म द्वारा संतुष्ट की जानी चाहिए जिनहै आय-कर आयुक्त, बॉम्बे बनाम द्वारका दास खेतान एंड कंपनी (5) में कहा गया है। यह प्रतिवादी के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।। तीसरा निर्णय आयकर आयुक्त बनाम बाग्यलक्ष्मी एंड कंपनी  है वहाँ जे. सुब्बा राव ने अदालत की ओर से बोलते हुए कहा हैः

"एक साथी एक संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता हो सकता है। वह एक न्यासी हो सकता है; वह एक उप-भागीदार बन सकता है। दूसरों के साथ जहाज; वह, एक समझौते के तहत, व्यक्त कर सकता है वह दूसरे के लिए बेनामीदार हो सकता है। ऐसे सभी मामलों में वह दोहरी स्थिति में है। क्या साझेदारी वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करता है; तृतीय पक्षों के लिए, अपनी प्रतिनिधि. क्षमता में। तीसरे पक्ष, जो भागीदारों में से एक प्रतिनिधित्व करता है, अन्य भागीदारों के खिलाफ अपने अधिकारों को लागू नहीं कर सकता है और न ही अन्य भागीदार उक्त तीसरे पक्ष के खिलाफ ऐसा कर सकते हैं। उनका अधिकार केवल अपने साथी के लाभ में एक हिस्से का है-कानून के अनुसार या समझौते की शर्तों के अनुसार, जैसा भी मामला हो।"

इन टिप्पणियों पर ही प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मजबूत रूप से निर्भरता रखी गई है। ये टिप्पिणियां इस तथ्य पर आधारित है कि वह व्यक्ति जिसे पंजीकरण की मांग कर रही फर्म में साझीदार के  रूप में स्वीकार किया गया था उसे व्यक्तिगत तौर पर ही स्वीकार किया गया था । यह उन परिस्थितियों में एवं स्पष्ट  रूप से इस प्रकार के मामलों में लागू नहीं हो सकती हैं जहां पर एक साझेदार दूसरे साझेदारों की जानकारी से कई व्यक्तियों की तरफ से और उनका प्रतिनिधित्व करते हुए जुड रहा हो। वास्तव में इस परिस्थिति के संयुक्त प्रभाव को इस प्रकरण की स्थापित परिस्थितियों के साथ निर्धारित किया जाना है। यह कानून का प्रश्न है और मैं स्पष्ट हूं कि यह प्रश्न सुलझने से कोसों दूर है और यह भी कि यह कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

इस मामले के विशेष तथ्यों पर एक और सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या रूपर फर्म का कानूनी अस्तित्व कहा जा सकता है क्योंकि इसके वास्तविक भागीदार केवल 14 व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि उस संख्या के अलावा 7 व्यक्ति हैं। के प्रावधानों के तहत एस. 11 कंपनी अधिनियम, 1956 (ओं. 1913 के अधिनियम का 4) जहां भागीदारों की संख्या 20 से अधिक है, फर्म को निगमित किया जाना है और यह स्वीकार किया जाता है कि यहां ऐसा नहीं किया गया है। यदि, इसलिए, संख्या 20 से अधिक है जो फर्म अनिगमित है, तो इसे कानूनी अस्तित्व नहीं कहा जा सकता है। दुर्भाग्य से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस मामले के तथ्यों और परिपथ स्थितियों पर चर्चा नहीं की है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा दायर दूसरी अपील को इस संक्षिप्त आधार पर खारिज कर दिया है कि उसके द्वारा उद्धृत निर्णयों को देखते हुए इसमें कोई योग्यता नहीं थी। यह आवश्यक था किन्यायाधिकरण यह पता लगाने के लिए कि क्या इस मामले के तथ्यों पर उन फैसलों ने मामले को समाप्त किया। जो प्रश्न उठते हैं, मेरी राय में, वे पक्षों के बीच महत्वपूर्ण हैं और उनका समाधान नहीं किया गया है। इन कारणों से मैं अपील की अनुमति देता हूं,

उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करता हूं और न्यायाधिकरण को प्रश्न को संदर्भित करने का निर्देश देता हूं। इससे पहले वे उच्च न्यायालय गए थे। अब तक की गई लागत परिणाम का पालन करेगी।

आदेश

बहुमत की राय के अनुसार, 1963 की सिविल अपील संख्या 605 को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। सिविल अपील सं। 810 और 811 को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

नोटः- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी यशस्वी शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवाहरिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होना और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।